www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 298 || लखनऊ
रविवार
01 फ़रवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
दैनिक
तमसा संकेत
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:52
सूर्यास्तः 05:48
अधिकतमः 23°00
न्यूनतमः 12°00

पेज 03

विशेष समाचार
सालिसिटर जनरल की चुप्पी? ... >> पेज 02
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम ... >>पेज 04
51 साल की हुईं प्रीति जिंटा ...

सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनीं

12 मिनट का शपथ ग्रहण, शरद पवार नहीं पहुंचे

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई/बारामती। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार शनिवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गईं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोकभवन में सुनेत्रा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला। शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे। इससे पहले दिन में NCP विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की विधान भवन में बैठक बुलाई गई थी। जिसमें सुनेत्रा को पार्टी नेता चुना गया था। डिप्टी CM की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। अजित पवार की तीन दिन पहले 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद डिप्टी CM पद खाली हो गया था।

राज्यपाल ने सुनेत्रा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई।

- मीटिंग के दौरान मौजूद सुनील तटकरे, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत बाकी नेता।
- शपथ ग्रहण समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे।

पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी

पीएम ने X पर लिखा, सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला हैं। मुझे विश्वास है कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी और स्वर्गीय अजित दादा के विजन को पूरा करेंगी। मुंबई में सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बीच सांसद सुप्रिया सुले अजित पवार की मां आशाताई पवार से मिलने के लिए काटेवाड़ी पहुंचीं। महाराष्ट्र विधान परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन डॉ. नीलम गोर्हे सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए लोक भवन पहुंचीं।

छगन भुजबल बोले- हम सभी अब मुख्यमंत्री से मिलेंगे

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुना गया है। अब हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। सुनेत्रा पवार को NCP विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद NCP नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। NCP के सभी विधायकों को शाम 4:30 बजे राजभवन के लोकभवन में बुलाया गया है। यहीं पर सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगी।

हाजीपुर का नया नाम सियारामपुर और उरमुरा किरार हुआ हरिनगर

सीएम योगी ने बदले दो गांवों के नाम

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले यूपी के दो जिलों में एक ग्राम पंचायत और एक गांव का नाम बदलने का फैसला लिया है। इनमें पहला जिला हरदोई है, जहां विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम बदलकर सियारामपुर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा जिला फिरोजाबाद है। यहां जिले की तहसील और विकासखंड शिकोहाबाद में पड़ने वाली ग्राम पंचायत वासुदेवमई के तहत आने वाले गांव उरमुरा किरार का नया नाम बदलकर हरिनगर कर दिया गया है। सियारामपुर के नए नाम से पहचानी जाने वाली ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। जिले के अंतर्गत भरावन विकास खंड है और इसी में हाजीपुर के नाम से यह ग्राम पंचायत थी, जिसका नया नाम अब सियारामपुर होगा। गांव में रहने वाले ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से हाजीपुर का नाम सियारामपुर करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिसपर योगी सरकार ने शनिवार को अपनी सहमति दे दी। हरिनगर अब उरमुरा किरार गांव का नया नाम होगा। यह गांव उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तहसील और विकासखंड शिकोहाबाद के अंतर्गत आता है।

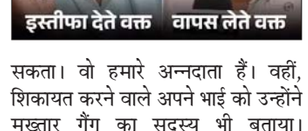

सुनेत्रा के बेटे पार्थ पवार ने शरद को समारोह में आने का न्योता दिया

पार्थ पवार ने बारामती में शरद पवार के घर जाकर उन्हें मनाया। पार्थ ने सुप्रिया सुले से भी बात की। शरद पवार को पार्थ पवार ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। हालांकि शरद पवार कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है।

जुलाई 2023 में जब अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हुए तब वित्त मंत्रालय फडणवीस ने अजित पवार को सौंप दिया था। वे 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करने वाले थे। फडणवीस के पहले कार्यकाल (2014-2019) में वित्त मंत्रालय सुधीर मुनगंटीवार के पास था। जुलाई 2023 में जब अजित पवार महायुति सरकार में शामिल हुए तब वित्त मंत्रालय फडणवीस ने अजित पवार को सौंप दिया था।

लोकभवन में 13 महीने 26 दिन बाद फिर शपथग्रहण समारोह

महाराष्ट्र के लोकभवन में पिछली बार 5 दिसंबर 2024 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्य-मंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने शपथ ली थी। अब इसी लोकभवन में 13 महीने 26 दिन बाद अजित की पत्नी सुनेत्रा का शपथ ग्रहण हो रहा है। डिप्टी सीएम की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। सुनेत्रा 18 जून 2024 को राज्यसभा सांसद बनीं थीं।

संजय निरुपम ने कहा- एनसीपी के फैसलों का सम्मान करना चाहिए

शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा,'यह एनसीपी का आंतरिक मामला है। सभी विधायकों और एनसीपी नेतृत्व का मानना था कि अजित दादा के निधन से खाली पद को तुरंत भरा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इस विचार का सम्मान किया जाना चाहिए और इस पर अनावश्यक विवाद नहीं होना चाहिए। एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय की रिपोर्ट्स पर उन्होंने कहा,'दोनों एनसीपी का विलय उनका आंतरिक मामला है। इस विषय पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए।'

शरद पवार बोले- अजित विलय चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए

अजित के निधन के बाद शरद पवार ने पहली बार सुनेत्रा के शपथग्रहण और NCP के दोनों गुटों के विलय पर बयान दिया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद ने कहा- ₹डिप्टी सीएम पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम दिए जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। उनकी पार्टी ने फैसला किया होगा। मैंने आज अखबार में देखा ।प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम हैं जिन्होंने कुछ फैसले लेने की पहल की है। शरद ने यह दावा भी किया कि दोनों गुटों को एकजुट करना उनके दिवंगत भतीजे अजित पवार की इच्छा थी, और वे इसके बारे में आशावादी थे। शरद ने कहा- "अब हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अजित पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी, दुर्भाग्य से, अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए।"

अजित के निधन के बाद अब लगभग यह तय है कि महाराष्ट्र का वित्त विभाग फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा और मार्च में सीएम ही महाराष्ट्र का बजट पेश करेंगे। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब उपमुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त दोनों महत्वपूर्ण विभाग थे। फडणवीस ने 9 मार्च 2023 को महाराष्ट्र राज्य का बजट भी पेश किया था।

जीएसटी अफसर प्रशांत ने वापस लिया इस्तीफा

विकलांगता पर क्लीन चिट का दावा झूठा निकला

पलटफेर

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या। अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा वापस ले लिया है। 4 दिन बाद फैसले से पलटने वाले अफसर ने कहा- मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। फिलहाल मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा हूं। उन्होंने 27 जनवरी को सीएम योगी का सपोर्ट करते हुए इस्तीफा दिया था। अफसर ने प्रयागराज माघ मेले में की गई शंकराचार्य की टिप्पणी पर जवाब दिया था। कहा था- मैं योगीजी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता। ठेला गाड़ी (पालकी) पर बैठकर कोई सीएम को उल्टा-सीधा नहीं कह सकता। वो हमारे अन्नदाता हैं। वहीं, शिकायत करने वाले अपने भाई को उन्होंने मुख्तार गैंग का सदस्य भी बताया। जीएसटी अफसर पर भाई ने नौकरी पाने के लिए विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाया था। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें इस मामले में मऊ सीएमओ से क्लीन चिट मिल गई है। जबकि, सीएमओ ने इस दावे को गलत बताया है।

इस्तीफा देते वक्त | वापस लेते वक्त

फास्ट न्यूज

बलूचिस्तान में एकसाथ 12 जगहों पर बलूचों का हमला

क्वेटा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक साथ 12 जगहों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक हमलों में कम से कम 10 सुरक्षाकर्मी और कम से कम 11 आम नागरिकों की मौत हुई है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर जिले में शनिवार सुबह 12 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमले किए।

प्रॉपर्टी के लिए मां-बाप और बहन का मर्डर

बेंगलुरु। कर्नाटक के विजयनगर जिले में पुलिस ने शनिवार को 24 साल के युवक को माता-पिता और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हत्या के बाद तीनों के शवों को कोट्टूर स्थित उनके किराए के घर में दफना दिया था। तिलकनगर थाने की पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि कोट्टूर निवासी आरोपी अक्षय कुमार ने 29 जनवरी को बेंगलुरु के तिलकनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके माता-पिता और बहन लापता हैं। इसके बाद खुद पुलिस के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने का नाटक करता रहा। जांच के दौरान आरोपी ने अलग-अलग बयान दिए, जिससे पुलिस को शक हुआ।

ट्रम्प के फायदे के लिए मोदी इजराइल में नाचे : पवन खेड़ा

एपस्टीन फाइल्स शेयर करके पूछा- पीएम ने यौन अपराधी से क्या सलाह ली

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने X पोस्ट में लिखा- यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। पीएम मोदी हमारे 3 सवालों का सामने आकर जवाब दें। खेड़ा ने लिखा- जेफ्री एपस्टीन को अमेरिका में मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार का दोषी ठहराया है, वो लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी सलाह मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच-गाना किया। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात हुई थी और यह काम कर गया। खेड़ा ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि भारत के पीएम का ऐसे बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना, उनके फैसलों, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब यह साफ है कि पीएम का एपस्टीन के साथ सीधा संबंध रहा है, जिसकी अब तक कोई साफ वजह सामने नहीं आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 तक इजराइल के दौरे पर गए थे। यह दौरा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर हुआ था। यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गए थे। इस दौरान मोदी ने नेतन्याहू से दोनों देशों के रिश्तों और सहयोग पर बात की। उन्होंने राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन से भी मुलाकात की। हाइफा में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और तेल अवीव में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। यह दौरा भारत-इजराइल संबंध के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

>> (शेष पेज 04 पर)

मेल में लिखा- निशाने पर डेरा बल्लां, 4 स्कूलों में आज धमाका, आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलेगा

पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले ब्लास्ट की धमकी

अलर्ट

तमसा संकेत, एजेंसी

जालंधर। PM नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से एक दिन पहले (31 जनवरी को) जालंधर के 4 स्कूलों में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही थाना-7 अर्बन एस्टेट पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने कहा कि पहले कैंब्रिज स्कूल को धमकी मिली थी। अब 3 और स्कूल- पठानकोट चौक के पास स्थित केएमवी संस्कृति स्कूल, ब्रिटिश ओलिवा स्कूल और सीजेएस पब्लिक स्कूल को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। हालांकि जांच के इस दौरान कुछ नहीं मिला है। आज गुरु रविदास महाराज की जयंती पर शोभायात्रा के चलते जालंधर के स्कूलों की छुट्टी है। कैंब्रिज स्कूल को भेजे गए ईमेल में लिखा गया है कि मोदी के दौरे को लेकर बम ब्लास्ट होगा।

>> (शेष पेज 04 पर)

> पीएम के दौरे से पहले डीजीपी गौरव यादव जालंधर पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया। डीजीपी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जालंधर दौरे से पहले शुक्रवार दोपहर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

जालंधर भाजपा कोर कमेटी ने मीटिंग की

जालंधर बीजेपी की कोर कमेटी ने पीएम के स्वागत को लेकर मीटिंग की। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक केडी भंडारी ने बताया पीएम 1 फरवरी को आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह डेरा बल्ला में माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के जालंधर आने से भाजपा वर्करों को एनर्जी मिलेगी।

जिला 1 फरवरी तक नो फ्लाइंग जोन रहेगा

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक जिला जालंधर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

जो रह जाएंगे उनको भाजपा का सीएम निकाल देगा, ये साल टीएमसी को 'टाटा, बाय-बाय' कहने का है

बंगाल में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे : शाह

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में कहा कि, ममता सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। बंगाल के लोग TMC को उखाड़ फेकेंगे। इनकी विदाई का समय आ गया है। ममता जी को SIR का जितना विरोध करना हैं कर लें। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा। जो बचे घुसपैठिये रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। साल 2026 TMC को 'टाटा, बाय-बाय' कहने का साल है। अमित शाह दो दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वे शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे। नॉर्थ परगना के बैरकपुर में रैली को संबोधित करने के बाद वे दोपहर 2 बजे बागडोगरा चले जाएंगे। जहां वह उत्तर बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ एक संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। एक महीने के अंदर राज्य में शाह का दूसरा दौरा है। इससे पहले 30 और 31 दिसंबर को शाह कोलकाता गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। आनंदपुर गोदाम में लगी आग चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि इसमें ममता बनर्जी के लोग शामिल हैं। अगर ममता बनर्जी इसे छिपाना चाहती हैं।

शाह की स्पीच, 6 बड़ी बातें...

- साल 2026 TMC को 'टाटा, बाय-बाय' कहने का साल है। TMC तो कम्युनिस्टों से भी आगे निकल गई है। जब मैं पहले आया था, तो मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से BJP की सरकार बनेगी। उस समय ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थीं। लेकिन जब भगवान राम ने राम सेतु बनाया था, तो रावण ने भी इसी तरह उनका मजाक उड़ाया था।
- 2024 में तीन दशक के बाद पहली बार मोदी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। हमने ओडिशा में सरकार बनाई। अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई। 2025 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते-आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा और एनडीए की सरकार बनी।
- जितने भी लोग आजादी के संघर्ष में शहीद हुए, जिन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया उनका आखिरी शब्द भी वंदे मातरम् ही था। मोदी सरकार ने वंदे मातरम् के 150 साल पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया है।
- मगर विडंबना देखिए कि वंदे मातरम् का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। उसी वंदे मातरम् पर जब संसद में चर्चा हो रही थी, तो ममता बनर्जी के सांसद उस चर्चा का विरोध कर रहे थे।
- आनंदपुर में लगी आग कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान चली गई है, और 27 लोग लापता हैं। यह घटना क्यों हुई? इस मोमो फैक्ट्री में किसका पैसा लगा है? मोमो फैक्ट्री के मालिक कौन हैं?
- आनंदपुर गोदाम में लगी आग चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि इसमें ममता बनर्जी के लोग शामिल हैं। अगर ममता बनर्जी इसे छिपाना चाहती हैं, लेकिन अप्रैल के बाद, जब बीजेपी सरकार आएगी, तो हम इस आग के दोषियों को चुन-चुनकर जेल भेजेंगे। दरअसल 26 जनवरी को आनंदपुर में एक फैक्ट्री में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी।

सीतारमण 75 साल की बजट परंपरा बदलेंगी

नई दिल्ली। एक फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपने बजट भाषण के भाग-बी (Part B) में भारत की इकोनॉमी के भविष्य को लेकर विस्तृत विजन पेश कर सकती हैं। अब तक के केंद्रीय बजटों में अधिकांश अहम बातें भाग-ए (Part A) में होती थीं।

अजित चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हों : शरद पवार

सब कुछ तय था, 12 फरवरी को ऐलान होना था

बातचीत

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर शरद पवार ने शनिवार को कहा, 'यह अजित पवार की भी इच्छा थी। इसे जरूर पूरा होना चाहिए।' शरद ने कहा कि अजित, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय के बारे में बातचीत शुरू की थी। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था लेकिन दुर्भाग्य से, अजित उससे पहले हमें छोड़कर चले गए। सूत्रों के मुताबिक अजित ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आया है। इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजित की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उधर शरद पवार के बारामती घर पर शनिवार सुबह पवार परिवार की बैठक हुई। इस बैठक में सुप्रिया सुले, रोहित पवार, युगेन्द्र पवार और शरद पवार शामिल हैं। इसके अलावा शरद गुट के नेता भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। अजित पवार एक काबिल और समर्पित नेता थे जिन्होंने सच में लोगों के लिए काम किया। वह लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे।

>> (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

योजनाओं के कुशल निष्पादन से परिभाषित होगा आने वाला दशक

पिछले एक दशक में भारत के आर्थिक कायाकल्प को सामान्य तौर पर जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों से ही रेखांकित किया जाता है, लेकिन ऐसा करना इस पूरी कहानी को समझने का अधूरा प्रयास ही कहा जाएगा। भारत में आकार ले रहा परिवर्तन विकास की गति से अधिक उसकी प्रकृति एवं स्वरूप में आया बदलाव अधिक महत्वपूर्ण है। देश ने एक नाजुक और असंतुलित अर्थव्यवस्था से एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए हैं, जो पूंजीगत व्यय, डिजिटल आधारभूत ढांचे और संस्थागत क्षमताओं पर आधारित है। हाल के वर्षों में राज्य क्षमता विस्तार, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण और उनकी नागरिकों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय निवेश देखा गया है। अब चुनौती इन बुनियादी परिवर्तनों को दीर्घकालिक उत्पादकता और समावेशी लाभों में बदलने की है। निःसंदेह श्रम बाजार का औपचारीकरण बढ़ा है, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कौशल के स्तर पर अभी भी अवरोध कायम हैं। वेतन आंकड़ों के हालिया रुझान को देखें तो हाल के वर्षों में औसतन बीस लाख नए कर्मियों का मासिक जुड़ाव सामने आया है। यह दर्शाता है कि डिजिटलीकरण और कर सुधारों ने व्यवसायों को औपचारिक स्वरूप अपनाने के लिए प्रेरित किया है। बेरोजगारी दर का पांच प्रतिशत के आसपास स्थिर रहना भी मजबूती और स्थायित्व का संकेत है। फिर भी यह परिवर्तन पहला चरण ही है, क्योंकि केवल औपचारिक रोजगार पर्याप्त नहीं हैं। स्थितियां तब तक नहीं सुधरेंगी, जब तक रोजगार की उत्पादकता और गुणवत्ता समान रूप से नहीं बढ़ती। महिला श्रम भागीदारी का लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंचना हौसला जरूर बढ़ाता है, पर इसका एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण, कम-भुगतान या अवैतनिक कार्यों में केंद्रित है। इसलिए अगला कदम रोजगार की गुणवत्ता और कौशल-आधारित प्रगति पर होना चाहिए, जिसके लिए कौशल प्रमाणन, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स नीति एक बाजी पलटने वाली सफलता के रूप में उभरी है। मात्र एक दशक में भारत मोबाइल फोन आयातक से घरेलू उत्पादन केंद्र में रूप में उभरा है। 2015 में 11.1 लाख करोड़ के रिकार्ड सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और नीतिगत सहायता ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को पिछले ग्यारह वर्षों में 11 गुना बढ़ाकर 4.15 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। इससे यह धारणा ध्वस्त हुई कि भारत औद्योगिक नीति को लागू नहीं कर सकता। हालांकि यह सफलता एक सीमा भी उजागर करती है। अभी भी जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत के आसपास है और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के सहारे ही व्यापक रोजगार सृजन संभव नहीं। टेक्सटाइल, फुटवियर एवं खिलौना जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में इस प्रकार की सफलता अभी प्राप्त होती नहीं दिख रही। ऐसे में, राज्य प्रोत्साहनों का उचित संयोजन, एमएसएमई अनुपालन सरलीकरण तथा लाजिस्टिक्स एवं बंदरगाह दक्षता में सुधार इस मोर्चे पर सफलता की ओर उन्मुख कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कारोबारी सुगमता में सुधार ने भी निवेश को गति प्रदान की है। पुराने कानूनों को हटाने, डिजिटल स्वीकृतियां और फेसलेस अनुपालन ने संचालन एवं विस्तार को अधिक सुगम बनाया है। जीएसटी के तहत 1.4 करोड़ व्यवसायों का जुड़ना प्रशासनिक सरलीकरण की गहराई को दर्शाता है। फिर भी छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए जमीनी अनुभव मिले-जुले हैं। वहां अनुपालन तो डिजिटल हुआ है, पर अपेक्षित रूप से सरलता संभव नहीं हो पाई है। केंद्र-राज्यों के बीच नियामकीय परतें, नियमों में परिवर्तन तथा भूमि एवं श्रम औपचारिकताएं विस्तार की लागत बढ़ाती हैं। इसलिए सुधार के अगले चरण का केंद्र पूर्वानुमानिता, नियमों की स्थिरता और विवाद निपटान की तीव्रता होनी चाहिए। नियम कम होने चाहिए और जो हों, उनमें स्थिरता का भाव हो और उनका बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। भारत ने पिछले दशक में गरीबी घटाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। करीब 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस दौरान गरीबी सूचकांक 11.28 प्रतिशत तक गिरा है। यह आम नागरिकों की बेहतर जिंदगी का प्रमाण है। इसके बावजूद खपत का स्तर एकसमान नहीं है। कारों और ब्रांडेड सामान की खपत तेजी से बढ़ी है, जबकि सस्ती दैनिक जरूरतों की खपत में बढ़ोतरी अपेक्षाकृत धीमी रही। इसी अंतर को अक्सर बढ़ती असमानता कहा जाता है, लेकिन विकास में यह सही क्रम भी है। इस लिहाज से अब अगली चुनौती आय में स्थिरता नहीं, बल्कि आय की गतिशीलता से संबंधित है। कल्याणकारी योजनाओं को कौशल प्रशिक्षण, छोटे ऋण, स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर और शहरों के रोजगार कॉरिडोर से जोड़कर लांचपैड बनाया जा सकता है। बीते एक दशक में भारत ने डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे, राजकोषीय क्षमता और संस्थागत निर्माण को मजबूती प्रदान की है। इसका अर्थ है कि सुधारों की गति और दायरा बढ़ा है। अब आने वाला दशक बड़ी घोषणाओं से नहीं, बल्कि पूर्व की योजनाओं के कुशल निष्पादन से परिभाषित होगा। यह निष्पादन केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्यों, नगर निकायों, निजी उद्यमों और संस्थानों की सामूहिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

सालिसिटर जनरल की चुप्पी?

डॉ0 ओ0पी0 मिश्र

“ यहां की घटनाएं उन छात्रों पर प्रभाव डालती है जिन्हें भविष्य में देश और समाज की दिशा तय करनी है । इसलिए यहां आवश्यक यह है कि कोई भी नियम कानून की मेरिट और डिमैरिट परखने तथा सोच समझ के बाद ही लागू किया जाए।

हम सब जानते हैं कि किसी भी मुकदमे में दो पक्ष होते हैं एक तरफ सरकार का पक्ष रखने तथा सरकार को डिफेन्ड करने के लिए सरकारी वकील तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष का वकील जो यह साबित करने का प्रयास करता है कि उसके क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया बल्कि उसी के साथ गलत किया गया। निकली आदालतो में इन्हीं सरकारी वकील को कोर्ट साहब यानि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अर्थात अभियोजन अधिकारी कहा जाता है । जबकि आगे बढ़ने पर यानी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर इन्हें एडवोकेट जनरल, सालिसिटर जनरल कहा जाता है । अमूमन यह सारे विधि वेत्ता सरकार के निर्णय तथा उसकी पॉलिसी कैसे को सही सिद्ध करने का ही प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि यह उनका दायित्व है। लेकिन प्रत्येक भारतवासी को उस समय अचरज हुआ जब यूजीसी को लेकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया और वहां मौजूद सरकार के वकील यानी सालिसिटर जनरल ने चुप्पी साध ली? क्यों चुप्पी साथ ली, किसके कहने पर चुप्पी साध ली और उनकी चुप्पी की वजह क्या थी? यह कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब तो आना ही चाहिए। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही क्या सरकार वोट बैंक सहेजने के चक्कर में खुद ही फस गई थी? क्या सरकार को यह लग गया था कि इस तरह तो अगडे और पिछडे दोनों उसके हाथ से जाएंगे? क्या इसीलिए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता खामोश रहे? कितनी अजीब बात है कि जब-जब सीजेआई सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुखातिब हुए और स्पष्टीकरण चाहा तब तब उन्होंने चुप्पी साध ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है क्या हम फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं? सालिसिटर जनरल चुप रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए। इसके लिए आपके पास क्या कोई सुझाव है? तुषार मेहता चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में ये नियम अस्पष्ट है। य समाज को बांट देंगे और खतरनाक प्रभाव भी पड़ेगा। सालिसिटर जनरल चुप रहे। फिर कोर्ट ने कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए जो इसकी समीक्षा करें। मेहता साहब चुप ही रहे। यहां यह जानना आवश्यक है कि 13 जनवरी को यूजीसी ने कथित समानता का यह आदेश promotion of equity in higher education institutions regulations को लागू किए जाने का आदेश दिया था। जिसे मात्र 15 दिनों बाद यानी 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी काफी जल्दबाजी में था और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की छुप्पी यह बता रही थी कि वह चाहते हैं कि फिलहाल तुरंत स्टे लग जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट कभी भी इतनी एक्टिव नहीं हुई है। याद कीजिए सी ए ए पर आज तक रोक नहीं लगी? बिहार चुनाव के समय S I R की घोषणा हुई थी आधा दर्जन राज्यों ने इसका विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। क्योंकि सालिसिटर जनरल तुषार मेहता इन मामलों में खामोश नहीं रहे। जबकि यूजीसी के मामले में वह खामोश रहे और बहस नहीं की कि यह एक वर्ग को सुरक्षित महसूस करने के लिए क्या दूसरे वर्ग को असुरक्षित करना आवश्यक है। यहां यह बात भली-भांति समझनी होगी की शैक्षणिक परिसर सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है। यहां की घटनाएं उन छात्रों पर प्रभाव डालती है जिन्हें भविष्य में देश और समाज की दिशा तय करनी है । इसलिए यहां आवश्यक यह है कि कोई भी नियम कानून की मेरिट और डिमैरिट परखने तथा सोच समझ के बाद ही लागू किया जाए। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देश को जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए ना के पीछे की तरफ तो सही ही कहा। लेकिन सरकार और सरकारों की नीतियां हमेशा जाति के आधार पर ही तय होती आयी हैं। क्योंकि सारे राजनीतिक दल जाति आधारित ही राजनीति करते हैं। टिकट जाति के आधार पर बांटे जाते हैं, मंत्री जाति के कोटे के आधार पर बनाए जाते हैं वोट के लिए और चुनाव जीतने के लिए। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की जाति बताई जाती है फिर हम जाति विहीन समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर मैं यह कहूं कि हमारे जिस्म

के रगों में बहते हुए खून की रंगत भी जाति के रंग से रंगी है तो शायद गलत नहीं होगा । यह बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूजीसी कानून भी जाति के पोषण के लिए ही शायद लाया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह भारत सरकार का कानून है संसद का कानून है सभी को इसे मानना ही पड़ेगा। इस मौके पर मैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वह बयान यहां कोड कर रहा हूं जिसमें वह कहते हैं कि सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रति हार्दिक आभार। आज मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं लेकिन मंत्री जी को यह भी तो बताना चाहिए की 13 जनवरी को जब यह लागू हो रहा था तो वह कहां थे और क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सुनना चाहिए जिसमें वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला देश के लिए सम्मान और खुशी की बात है। एक अन्य बयान में केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि मोदी जी और हमारी पार्टी अंतिम सांस तक यूजीसी कानून लागू करने के लिए लड़ते रहेंगे। दलित, पिछड़े आदिवासी सभी लोग हमारे ऊपर भरोसा रखिए। अब देखना यह होगा कि किसके भरोसे पर मोदी जी और भाजपा खरी उतरती है। क्योंकि वोट तो सरकार बनाने के लिए अगड़े पिछड़े तथा दलित सभी का भाजपा को चाहिए। लेकिन यूजीसी लागू करके शायद ही भाजपा सबको खुश कर पाए? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना है कि नए नियमों का दुरुपयोग संभव है । इसी के साथ ही सरकार को भी यह समझना जरूरी है कि स्वर्ण में किन बातों को लेकर नाराजगी है। इतना ही नहीं नियमों के क्रियान्वन की जिम्मेदारी कुलपतियों तथा प्राचार्यो को भी लेनी होगी। तभी बात बन पाएगी। इसके विपरीत यूजीसी समर्थकों का कहना है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों द्वारा सामान्य वर्ग से भेदभाव का कोई मामला नहीं है। लेकिन भविष्य में रोहित वेमूला तथा पायल तड़वी जैसी घटनाएं न घटे और कोई आत्महत्या करने के लिए विवश न हो । इसलिए नियमों को चुस्त दुरुस्त किया गया है। यूजीसी समर्थको का यह भी कहना है कि अधिकांश संस्थाओं के प्रमुख सामान्य वर्ग से आते हैं इसलिए सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय होने की संभावना कम है। खैर जो भी हो लेकिन बर्र के छत्ते पर पत्थर फेंकने का काम जो भाजपा ने किया है उसका खामियां आज तो उसे उठाना ही पड़ सकता है। क्योंकि दोनों को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। भाजपा अगर इस भ्रम में है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मनाने के लिए अंततः अगडे और पिछड़े दोनों मजबूर होंगे तो यह उसका दिवास्वप्न है। क्योंकि सालिसिटर जनरल की चुप्पी भी मलहम का काम कर पाएगी कहां नहीं जा सकता।

भारत के पास विशाल ... कमलेश पांडेय

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक : भविष्य के भारत की तलाश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि “भविष्य के भारत” की झलक भी मिलती है। बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास। सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी

अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यदि निम्न आय वर्ग की आय बढ़ती है, उसे सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग बढ़ने से उत्पादन, निवेश और रोजगार-तीनों को गति मिलती है। इसलिए इस बजट में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के साथ-साथ रोजगार सृजन के ठोस उपाय अपेक्षित हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, शहरी गरीबों के लिए भी समान प्रकृति की योजनाएं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

शहरी विकास इस बजट का एक और प्रमुख केंद्र होना चाहिए। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरों पर जनसंख्या, आवास, परिवहन, जल, स्वच्छता और पर्यावरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। केवल बड़े महानगरों पर निर्भरता अब व्यावहारिक नहीं रही। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा सुझाया गया शहरी विकेंद्रीकरण का विचार आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना, उद्योगों और सेवाओं को वहां प्रोत्साहित करना, न केवल महानगरों पर बोझ कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी घटाएगा। बजट में यदि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष शहरी अवसंरचना पैकेज, परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तो यह दूरगामी परिवर्तन का आधार बन सकता है। वैश्विक स्तर पर टैरिफ, व्यापार अवरोध और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां भारत के लिए चुनौती भी हैं और अवसर भी। अजय बंगा का यह कथन कि टैरिफ पर अधिक चिंता करने के बजाय व्यापारिक अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टि प्रदान करता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा जनसंख्या, डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की प्रबल ऊर्जा है। यदि यह बजट निर्यात-उन्मुख उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू-एडेड सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान बना सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को केवल नारों से आगे ले जाकर व्यावहारिक नीति समर्थन की आवश्यकता है-सरल कर संरचना, आसान ऋण, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश और व्यापार करने में सुगमता के माध्यम से। इस संदर्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती होगा। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है-वह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा करदाता भी। विडंबना यह है कि बजट चर्चाओं में अक्सर यही वर्ग अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, आवास ऋण और करों का बोझ मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग दोनों को प्रभावित करता है। यदि इस बजट में आयकर स्लैब में तर्कसंगत सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य पर कर राहत और आवास को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि मांग-आधारित विकास को भी बल मिलेगा। उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बजट से अपेक्षा है कि वह स्थिर और पूर्वानुमेय नीति वातावरण प्रदान करे। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं। कर नीति में बार-बार बदलाव, अनुपालन की जटिलता और नियामक अस्पष्टता निवेश को बाधित करती है। इस बजट में यदि दीर्घकालिक कर-नीति का स्पष्ट संकेत, एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ता ऋण, तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन और हरित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, तो यह उद्योगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, उसे आर्थिक पुनरुत्थान का केंद्र बनाया जाना चाहिए।

यह ग्रामीण रोजगार ... कमलेश पांडेय

विकसित भारत के दृष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मायने

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उच्च वृद्धि दर का अनुमान है। देखा जाए तो यह बजट 2026-27 से पहले नीतिगत दिशा तय करता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों पर जोर देता है। यही वजह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैसे नीतिगत सुधारों पर बल दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। कहना न होगा कि ये सभी सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं। जहां तक इस आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं की बात है तो इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि 7.4% और जीवीए 7.3% का प्रथम अनुमान दिया गया है, जबकि एफ वाई (FY) 2027 के लिए 6.8-7.2% का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। वहीं, निजी उपभोग (जीडीपी का 61.5%) और निवेश (30%) प्रमुख चालक हैं, साथ ही मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2025 में औसतन 1.7% रही। जबकि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष (FY) 2026 में 4.4% तक कम होने का लक्ष्य है, जो नीतिगत स्थिरता दर्शाता है। कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख क्षेत्रीय प्रदर्शन इस प्रकार हैं- क्षेत्र - मुख्य उपलब्धियाँ * विनिर्माण : उच्च-तकनीकी गतिविधियों का 46.3% योगदान है; जबकि मोबाइल उत्पादन में 30 गुना वृद्धि (FY15-FY25) हुई है। कृषि : खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मीट्रिक टन हो चुका है; जबकि पशुपालन में 6.1% वृद्धि दर्ज की गई है। सेवाएँ : जीवीए में 9.3% वृद्धि (H1 FY26) हुई है; जबकि वैश्विक निर्यात में 4.3% हिस्सा हो चुका है। बुनियादी ढांचा : राजमार्ग 60% बढ़े हैं; जबकि विदेशी मुद्रा

भंडार $701.4 अरब पर पहुंच चुका है। इसप्रकार ये आंकड़े उत्साहित करते हैं, क्योंकि जहां विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाऐं संघर्ष कर रही हैं, वही भारतीय अर्थव्यवस्था फर्राटे भर रही है। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के नीतिगत निहितार्थ की बात है तो यह सर्वेक्षण आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और रणनीतिक लचीलेपन पर जोर देता है, जिसमें पीएलआई (PLI) योजनाओं से 12.6 लाख नौकरियाँ सृजित हुई हैं। यह ग्रामीण रोजगार में मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी' मिशन और एआई (AI) तथा स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस सुझाता है, जो रोजगार-सघन विकास को बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर, यह उच्च वृद्धि, कम महंगाई और समावेशी नीतियों से 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को मजबूत बनाता है। कहना न होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उन नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है जो आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें। ये सुझाव वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीलेपन और संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित हैं। यदि ग्रामीण रोजगार सुधार की दृष्टि से देखा जाए तो मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025' की स्थापना का सुझाव दिया गया है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने... ललित गर्ग

शिक्षा में समता या नई असमानता: यूजीसी नियमों पर न्यायिक विराम

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के नाम पर लागू किए गए नए नियमों ने देश के शैक्षिक और सामाजिक परिदृश्य में एक बार फिर गहरी हलचल पैदा कर दी है। जिस नीति को ‘समता’, ‘समान अवसर’ और ‘समावेशी शिक्षा’ की भावना से जोड़कर प्रस्तुत किया गया, वह व्यवहार में आते ही एक वर्ग विशेष के तीव्र विरोध, व्यापक असंतोष और सामाजिक तनाव का कारण बन गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर इन नियमों पर अंतरिम रोक लगानी पड़ी। यह रोक न केवल सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया पर एक प्रश्नचिह्न है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण और असंतुलित प्रयोग देश को किस दिशा में ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसी नीति के समर्थन या विरोध का सीधा निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक चेतावनी है कि समानता के नाम पर लागू किए गए नियम यदि अस्पष्ट हों, दुरुपयोग की संभावना रखते हों और सामाजिक सौहार्द को बाधित करते हों, तो वे न्यायिक समीक्षा से परे नहीं रह सकते। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना कि यूजीसी के नए नियमों में स्पष्टता का अभाव है और यही अस्पष्टता उन्हें विवादास्पद बनाती है। यह रोक सरकार को आत्ममंथन का अवसर देती हैकुएक ऐसा अवसर जिसे राजनीतिक टकराव के बजाय सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि जो सरकार बार-बार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की बात करती रही है, वह शिक्षा संस्थानों जैसे विचार-निर्माण के केंद्रों में ऐसे नियम क्यों लाई, जिनसे जातिगत पहचान और वर्गीय

विभाजन की रेखाएँ और गहरी होने की आशंका पैदा हो गई। भारत का सामाजिक इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जाति के नाम पर की गई किसी भी नीति ने, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही कल्याणकारी क्यों न रहा हो, समाज को भीतर ही भीतर विभाजित किया है। आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए लाई गई थी, लेकिन इसके लंबे प्रयोग ने देश को ऐसे घाव भी दिए हैं, जिनका उपचार आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो सका। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आधार को और उभारने वाली किसी भी पहल को लेकर स्वाभाविक रूप से आशंका उत्पन्न होती है। शिक्षा संस्थान केवल डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां नहीं होते; वे समाज की दिशा तय करने वाली प्रयोगशालाएं होते हैं। यहां तैयार होने वाला छात्र केवल नौकरीपेशा व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का नागरिक होता है। यदि यही परिसर अविश्वास, वर्ग-संघर्ष और परस्पर शंका के केंद्र बन जाएं, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करता है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठा विरोध इसी आशंका का प्रकटीकरण है। यह भी विचारणीय है कि समानता और समता के बीच का अंतर नीति-निर्माण में किस हद तक समझा गया। समानता का अर्थ है सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जबकि समता का अर्थ है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित अवसर देना। यदि समता के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो एक नए प्रकार की असमानता को जन्म दें, तो वह नीति अपने उद्देश्य से भटक जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी बिंदु की ओर संकेत करती है कि नियमों का उद्देश्य भले ही सकारात्मक रहा हो, लेकिन उनकी संरचना और भाषा ने विवाद और भ्रम को जन्म दिया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग तेजी से हावी होता गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने-अपने हितों के चश्मे से देखना शुरू कर दिया, वोट बैंक की राजनीति से इसे देखा जाने लगा जबकि यह विषय मूलतः शिक्षा सुधार और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई अवसरों पर यह कहते रहे हैं कि शिक्षा को राजनीति से मुक्त रखा जाना चाहिए और नीतियां दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए इन नियमों में उस दूरदर्शिता और संतुलन का अभाव क्यों दिखा? लगता है कि यूजीसी ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इसे लागू कर दिया,यदि यूजीसी ने व्यापक संवाद, सभी पक्षों से परामर्श और संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं का पूर्व आकलन किया होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। नीति बनाते समय केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं होती; सामाजिक स्वीकार्यता और नैतिक संतुलन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश के माध्यम से यही संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी बदलाव से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। नए नियमों की सबसे बड़ी कमजोरी एवं त्रासदी यही रही कि वे आरक्षित और सामान्य वर्गों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करके विद्रोह एवं विरोध में खड़ा कर दिया। यह विभाजनकारी प्रवृत्ति न केवल शिक्षा के वातावरण को दूषित करती है, बल्कि उस राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को भी कमजोर करती है, जिसकी बात हम संविधान में करते हैं। किसी भी नीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह समाज को जोड़ती है या तोड़ती है। यदि वह अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देती है, तो उस पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक सुधार का अवसर है-सरकार, यूजीसी और समूचे शैक्षिक तंत्र के लिए। यह समय है कि भावनाओं और राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठकर एक ऐसी नीति बनाई जाए, जो वास्तव में समान अवसर सुनिश्चित करे, लेकिन बिना किसी नए विभाजन को जन्म दिए। शिक्षा में सुधार का अर्थ समाज को आगे ले जाना है।

वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्काराज से होगा मुकाबला, सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया

नोवाक जोकोविच 11वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में

नई दिल्ली, एजेंसी

सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जहां उसका सामना वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्काराज से एक फरवरी को दोपहर 2 बजे से होगा। 38 साल के जोकोविच ने मेंस सिंगल्स कैटेगरी के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से हराया। वे ओपन एरा में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। जोकोविच ने 11वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। वे 2023 के बाद खिताबी दौर में पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने 10 फाइनल खेले और सभी जीते हैं। जोकोविच अपने करियर के 25वें ग्रैंड स्लैम और 11वें ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल से एक जीत दूर हैं। फिलहाल वे मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी पर हैं। उन्होंने कहा- 'मैं पहले भी ऐसे मैच खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे इसमें दिल-जान लगा देनी थी। मैंने ऐसा ही किया और आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। पांचवें सेट में जिस तरह से मैंने वापसी की, उस पर मुझे खुद पर बेहद गर्व है।' विमेंस सिंगल्स फाइनल में आर्यना सबालेंका का सामना एलिना रायबकिना से होगा। यह मैच रॉड लेवर एरिना में 31 जनवरी को दोपहर 2:00 बजे से खेला जाएगा। टॉप सीड सबालेंका ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन की विमेंस सिंगल कैटेगरी के सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराया।

अल्काराज के पास करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का मौका

अल्काराज के ट्रॉफी कैबिनेट में अब तक का एकमात्र ग्रैंड स्लैम खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन ही बचा है। अगर वह इस साल मेलबर्न में जीत हासिल करते हैं, तो वह करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के मेंस प्लेयर बन जाएंगे। करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि किसी खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर के दौरान चारों ग्रैंड स्लैम कम से कम एक बार जीती हों। इन्हें एक ही कैलेंडर ईयर में जीतना जरुरी नहीं है।

जोकोविच गर्मी से परेशान दिखे। उन्होंने मैच के दौरान टी-शर्ट उतर दी थी।

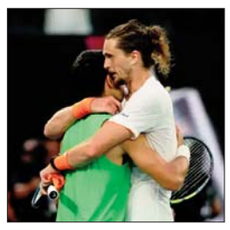

मैच के बाद अल्काराज को बधाई देते ज्वेरेव (सफेद टी-शर्ट में)।

अल्काराज पहली बार फाइनल में पहुंचे

वर्ल्ड नंबर-1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। चोट से जूझ रहे अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को पांच सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेला गया यह मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला, जिसमें अल्काराज ने ज्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 से हराया।

अल्काराज बोले- मुझे खुद पर बेहद गर्व है

जीत के बाद अल्काराज ने कहा- मैं हमेशा कहता हूं कि हालात चाहे जैसे भी हों, खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। तीसरे सेट में मैं संघर्ष कर रहा था। शारीरिक रूप से यह मेरे करियर के सबसे कठिन मुकाबलों में से एक था।

सैम करन टी-20आई में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंग्लिश क्रिकेटर

इंग्लैंड ने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई

नई दिल्ली, एजेंसी

इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले टी-20 मुकाबले में डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 11 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लिश टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बारिश के कारण मुकाबला तय समय पर शुरू नहीं हो सका, जिसके चलते ओवरों में कटौती कर इसे 17-17 ओवर का मैच कर दिया गया। शुक्रवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लिश गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 133 रन पर ऑलआउट कर दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बना लिए थे, तभी बारिश ने फिर से खलल डाल दिया और आगे का खेल संभव नहीं हो सका। डकवर्थ-लुईस नियम के अनुसार इंग्लैंड उस समय टारगेट से आगे था, जिसके चलते मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा। गेंदबाजी में सैम करन और आदिल रशीद ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें करन ने हैट्रिक ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद श्रीलंका की टीम 16.2 ओवरों में 133 रन पर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका की ओर से कुसल मेंडिस ने 37 जबकि पाथुम निसांका ने 23 रन बनाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें आदिल रशीद और सैम करन ने तीन-तीन विकेट चटकाए। सैम करन ने श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर दासुन शनाका, महीश तीक्षणा और माथीश पथिराना को आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की। वे टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। इससे पहले क्रिस जॉर्डन ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं, आदिल रशीद ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट झटके और इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा जेमी ओवरटन और लियाम डॉसन को भी दो-दो सफलता मिली। इंग्लैंड के लिए ओपनर फिलिप सॉल्ट ने 35 गेंदों में 46 रन, वहीं टॉम बैंटन ने 15 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए ईशान मलिंगा ने 2 विकेट, महीश तीक्षणा और कप्तान दसुन शनाका ने 1-1 विकेट लिया।

फास्ट न्यूज

आरकोम के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग गिरफ्तार

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। पुनीत पर अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के जरिए बैंकों के साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। शुक्रवार को ईडी ने बताया कि दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गर्ग को 9 दिनों की ईडी कस्टडी में भेज दिया है।

एपस्टीन फाइल्स में भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम

वॉशिंगटन। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार देर रात एपस्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी नई फाइल्स रिलीज की हैं। इनमें जेफ्री एपस्टीन के कुछ ईमेल सामने आए हैं। अमेरिकी मीडिया न्यू यॉर्क पोस्ट के मुताबिक फाइल्स में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर का नाम भी सामने आया है। मीरा नायर से जुड़ा मेल अमेरिकी फिल्म पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने एपस्टीन को 21 अक्टूबर 2009 को भेजी थी। इसमें पेगी सीगल ने लिखा है कि वह गिस्लीन मैक्सवेल (एपस्टीन की गर्लफ्रैंड और अपराधी) के मैनहट्टन टाउनहाउस से एक आफ्टर-पार्टी से लौटी हैं। मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की मां हैं। मैक्सवेल के घर पर हुई यह पार्टी मीरा नायर की 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'एमेलिया' से जुड़ी थी।

फास्टैग के लिए केवाईवी प्रोसेस आज से खत्म होगी

नई दिल्ली। नई कार, जीप और वैन के लिए कल (1 फरवरी) से फास्टैग जारी करते समय अब KYV (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही, जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रुटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्युमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जैकी चैन ने रिकॉर्ड किया फेयरवेल सॉन्ग

यह गाना एक्टर की मौत के बाद रिलीज होगा, दुनिया के लिए होगा उनका आखिरी संदेश

मुंबई। कुंग-फू फिल्मों के मशहूर एक्टर जैकी चैन ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने एक ऐसा गाना रिकॉर्ड किया है, जो उनकी मौत के बाद रिलीज किया जाएगा। उन्होंने इस गाने को दुनिया के लिए अपना आखिरी संदेश बताया। यह बात उन्होंने 28 दिसंबर को बीजिंग में अपनी नई ड्रामा फिल्म अनएक्सपेक्टेड फैमिली के प्रीमियर के दौरान कही। China.org.cn की रिपोर्ट के अनुसार, जैकी चैन ने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों और अपनों को खो दिया है। इन घटनाओं ने उन्हें जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन बहुत छोटा है और जो बातें दिल में हैं, उन्हें समय रहते कह देना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक खास गाना रिकॉर्ड किया है, जिसे वह अपना आखिरी संदेश यानी फाइनल मैसेज मानते हैं। इस गाने को रिकॉर्ड करने के पीछे उनकी भावना बहुत गहरी है। जैकी चैन ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हुई कई लोगों की मौतों ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। इसलिए उन्होंने सोचा कि दुनिया से विदा लेने से पहले वह अपनी भावनाएं एक गाने के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि, उनके परिवार और उनकी टीम ने इस गाने को अभी रिलीज न करने की सलाह दी है। इसलिए यह तय किया गया है कि यह गाना उनके फैंस के लिए उसी दिन जारी किया जाएगा, जब चैन इस दुनिया को अलविदा कहेंगे।

₹230 करोड़ से ज्यादा हुई बॉर्डर 2 की कमाई

नई दिल्ली। देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने सिर्फ 8 दिनों में 230 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। हालांकि, दमदार ओपनिंग वीकेंड के बाद वीकडेज में कमाई थोड़ी घटी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने एक हफ्ते में दुनियाभर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। सैकनिल्क के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने आठवें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को भारत में 11 करोड़ रुपए की कमाई की। सातवें दिन फिल्म ने 11.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 235.25 करोड़ रुपए हो चुकी है। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो भारत से ग्रॉस कमाई 281.5 करोड़ रुपए हुई है। विदेशों से फिल्म ने करीब 41 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 322.5 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस रफ्तार से फिल्म के दूसरे वीकेंड पर 350 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, फिल्म की शानदार सफलता का सनी देओल ने जश्न मनाया। सनी ने हिमाचल प्रदेश के मनाली के एक होटल में अपनी टीम के साथ केक काटा। जश्न के दौरान सनी काफी खुश नजर आए। केक पर "बधाई हो बॉर्डर 2" लिखा हुआ था।

अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ गवाही देने वाली इकलौती सेलिब्रिटी, मुफ्त के ₹600 करोड़ ठुकराए

51 साल की हुईं प्रीति जिंटा

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा आज 51 साल की हो गई हैं। फिल्म 'दिल से' से करियर की शुरुआत करने वाली प्रीति ने दिल चाहता है, कल हो ना हो, कोई मिल गया, वीर-जारा और कभी अलविदा ना कहना जैसी कई फिल्मों में काम किया। प्रीति का जन्म एक हिमाचली राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता दुर्गानंद जिंटा भारतीय सेना में अधिकारी थे। बचपन से पिता की डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल ने एक्ट्रेस की पर्सनैलिटी पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन जब प्रीति 13 साल की थीं, तब उनके पिता का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस कार में उनकी मां नीलप्रभा भी थीं। किस्मत से उनकी जान बच गई, लेकिन उनके शरीर की लगभग हर हड्डी, यहां तक कि रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। वह करीब एक साल तक बिस्तर पर रहीं। सिमी गरेवाल के शो में प्रीति ने पिता के साथ हुए हादसे को लेकर बताया था कि हादसे से कुछ दिन पहले उन्हें अजीब सा एहसास हो रहा था। वह स्कूल में रोज न्यूजपेपर पढ़ती थीं और एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त शगुन से कहा था कि न जाने क्यों उन्हें लगता है कि वे अपने

"प्रीति ने बताया था कि उस घटना पर उन्होंने महीनों तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। करीब छह महीने तक वह रोई तक नहीं। उन्हें कभी पिता का शव देखने नहीं दिया गया था, इसलिए उनके मन ने इस सच को स्वीकार ही नहीं किया। फिर एक रात अचानक नींद में उनकी चीख निकल गई और सारा दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ गया। अपने पिता को याद करते हुए प्रीति ने बताया था कि उन्होंने उन्हें हमेशा बराबरी का दर्जा दिया। वह कहते थे कि बेटियों को कमजोर बनाकर नहीं पालना चाहिए। अगर बेटे बैग उठाते थे, तो बेटी भी उठाती थी। अगर बेटी खाना बनाना सीखती थी, तो बेटे भी सीखते थे।"

भाई को झगड़े में पत्थर मार दिया था

प्रीति जिंटा बचपन से ही बहुत निडर और शरारती थीं। एक बार उनका अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया। गुस्से में उन्होंने पत्थर उठाकर भाई के सिर पर मार दिया। भाई रोने लगा। तब प्रीति को अपने पापा की बात याद आ गई। उनके पापा हमेशा कहते थे, "राजपूत रोते नहीं हैं।" बस फिर क्या था, प्रीति ने भाई को थप्पड़ मारकर कहा, "तुम राजपूत नहीं हो क्या? रोना बंद करो!" भाई के सिर से खून निकल रहा था, लेकिन वो चुपचाप बैठ गया। तभी मां आ गईं। प्रीति को पता था कि अब तो पिटाई पक्की है, इसलिए वो डर के मारे टेबल के नीचे छुप गईं। पूरी रात वो वहीं सोती रहीं। घरवालों को लगा कि प्रीति डरकर घर से भाग गई है। पुलिस तक बुला ली गई। सुबह जब घर साफ करने वाली बाई आई, तब पता चला कि प्रीति तो टेबल के नीचे ही सो रही थीं।

किताब नहीं थी, फिर भी सब्जेक्ट में टॉप किया

टीवी शो जीना इसी का नाम है में प्रीति की मां ने बताया था कि प्रीति स्कूल में तो खूब पढ़ती थीं, लेकिन घर आकर किताबें कम खोलती थीं। जब उनकी मां को दसवीं के इंग्लिश पेपर से एक दिन पहले पता चला कि प्रीति के पास इंग्लिश की किताब ही नहीं है, तो वो बहुत घबरा गईं और तुरंत बाजार से किताब लाकर दी। प्रीति को कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन मां को लग रहा था कि अब ये फेल हो जाएगी।

दिलचस्प तरीके से हुई करियर की शुरुआत

साल 1996 में प्रीति अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थीं। वहीं उनकी मुलाकात एक ऐड फिल्ममेकर कुणाल से हुई। बातों-बातों में कुणाल को प्रीति की पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई कि दो दिन बाद उन्होंने फोन कर कहा कि उन्होंने एक चॉकलेट का ऐड प्रीति को ध्यान में रखकर लिखा है और उन्होंने प्रीति को ऑडिशन के लिए बुलाया। लेकिन उन्होंने सोचा कि ऑडिशन देने से क्या नुकसान होगा? वहां बस चार-पांच लोग होंगे और बात खत्म हो जाएगी।

प्रीति ने सीधा कहा, "मैं ऑडिशन देने नहीं आई हूं।"

शेखर ने माइक लेकर सबके सामने बोल दिया कि ये लड़की ऑडिशन देने आई है, लेकिन घबरा गई है। प्रीति का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने आखिरकार ऑडिशन दे ही दिया। दो हफ्ते बाद शेखर कपूर ने उन्हें बुलाया और कहा, "क्या आप मेरे साथ ये फिल्म (ता रा रम पम पम) करेंगी?" प्रीति को यकीन ही नहीं हुआ, उन्होंने सिक्का उछाल करके फिल्मों में काम करने का फैसला किया। हालांकि, यह फिल्म नहीं बन पाई।

सिक्का उछाल फिल्मों में आने का किया था फैसला

प्रीति एक ऑडिशन के लिए गई थीं, तभी उनकी मुलाकात फिल्ममेकर शेखर कपूर से हुई। वो सीढ़ियों से उतर रही थीं, हाथ में दो किताबें थीं।

हॉलीवुड एक्ट्रेस ने मुगल बेगम नूरजहां का ताज-महल नेकलेस पहना

54 साल पहले अमेरिकी अभिनेत्री को उनके पांचवें पति ने गिफ्ट किया था

कैलिफोर्निया, एजेंसी

हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्गोट रॉबी ने बेगम नूरजहां का 400 साल पुराना नेकलेस (हार) पहना जिसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है। वह अपनी आगामी फिल्म 'वुथरिंग हाइट्स' के प्रचार के लिए बुधवार को रेड कार्पेट पर ग्लैमरस लुक में दिखीं। रॉबी ने लॉस एंजिल्स में फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर पर एक शानदार गाउन पहना था। यह लुक बेहद खूबसूरत और विंटेज स्टाइल का था, लेकिन असली सुर्खियां बटोरीं उनके नेकलेस ने। यह 69.42 कैरेट का हार्ट शेप का टेबल-कट डायमंड है और इसे गोल्ड और रूबी से बनी कार्टियर चेन में सेट किया गया है। इस नेकलेस की कीमत लगभग 8 मिलियन डॉलर (करीब 74 करोड़ रुपये) बताई जा रही है। यह नेकलेस 54 साल पहले, 1972 में अमेरिकी एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर के पांचवें पति रिचर्ड बर्टन ने उनके 40वीं जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। ताज महल डायमंड की असली कहानी और भी रोचक है। इसे मुगल सम्राट शाह जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां को गिफ्ट किया था। यह दिल के आकार का डायमंड 17वीं सदी का है, जिस पर फारसी भाषा में 'प्यार हमेशा बना रहता है' लिखा है। इस पर नूरजहां का नाम भी उकेरा गया है। बाद में यह उनके बेटे शाहजहां के पास पहुंचा, जिन्होंने इसे अपनी पत्नी मुमताज महल को दिया। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जिसके कारण इस डायमंड को ताज महल डायमंड कहा जाने लगा। नूरजहां मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बेगम थीं। कहा जाता है कि वह मुगल सम्राट जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। उन्होंने 1611 में मुगल सम्राट जहांगीर से शादी की। जहांगीर ने उन्हें पहले नूर महल (महल की रोशनी) और बाद में नूरजहां (दुनिया की रोशनी) का खिताब दिया। वह मुगल इतिहास में इकलौती ऐसी बेगम थीं जिनके नाम पर सिक्के ढाले गए, फरमान जारी किए गए और उन्होंने दरबार में जहांगीर के साथ बैठकर शासन चलाया। नूरजहां मुगल दरबार में फैशन और स्टाइल की रानी मानी जाती थीं। उन्होंने खुद डिजाइनर की तरह काम किया और कई नए फैशन ट्रेंड शुरू किए। उन्होंने नूरमहली ड्रेस जैसी खास पोशाकें डिजाइन कीं, जो हल्की, फ्लोरल पैटर्न वाली कॉटन और मलमल से बनी होती थीं। उन्होंने बदला किनारी, पंचतोलिया (पांच रंगों वाली महीन कपड़े) और दुदामी जैसे नए टेक्सटाइल और फैब्रिक्स को पॉपुलर किया।

कर्जसंकट : दूसरे देशों के सामने हमारा सिर झुका रहता है, उनकी शर्तें मानना हमारी मजबूरी

कर्ज मांगने में अब शर्म आती है : शहबाज

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती निर्भरता को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। न्यूज एजेंसी तमसा संकेत के मुताबिक शहबाज ने राजधानी इस्लामाबाद में कारोबारी नेताओं को संबोधित करते हुए माना कि देश की बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बार-बार विदेशी दौरों पर जाकर कर्ज मांगना पड़ा। उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनियाभर में पैसे मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कई बार हम उनकी शर्तों को 'ना' भी नहीं कह पाते।" पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन्हीं देशों के सहारे टिकी हुई है। यही देश विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने और भुगतान संतुलन संकट से बचाने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। उन्होंने माना कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर पर्याप्त काम नहीं हुआ। पाकिस्तान का निर्यात अब भी कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। सॉफ्टवेयर, कृषि और पशुपालन में संभावना है, लेकिन ढांचागत कमजोरियां और कम उत्पादकता विकास में बाधा हैं। देश पर कुल सरकारी कर्ज मार्च 2025 तक 76,000 अरब रुपये से ज्यादा हो चुका है।

पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर आबादी के करीब 45% तक पहुंच गई है। इसकी वजह महंगाई, बाढ़ और आर्थिक अस्थिरता है। बेरोजगारी दर करीब 7.1% हो चुकी है और 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2018 में जहां 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे।

शहबाज बोले- पाकिस्तान को अब दूसरे रास्ते तलाशने की जरूरत

शहबाज ने यह भी कहा कि कर्ज का बोझ देश की इज्जत पर भारी पड़ रहा है और अब वैकल्पिक आर्थिक रास्ते तलाशने की जरूरत है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान IMF से मदद और पुराने कर्ज को रोलओवर (आगे बढ़ाने) की कोशिश कर रहा है। पीएम शहबाज के बयान से जाहिर है कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है।

चीन ने पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश किया

चीन ने पाकिस्तान को राहत देने के लिए उसका कर्ज लौटाने की समय-सीमा बढ़ा दी है। साल 2024-25 में यह मदद करीब 4 अरब डॉलर की मानी जा रही है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान में बिजली परियोजनाओं, सड़कों, बंदरगाहों और दूसरे ढांचागत कामों में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।

आईफोन 18 लॉन्चिंग इस साल टल सकती है

नई दिल्ली। टेक कंपनी एपल आमतौर पर हर साल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज के चार मॉडल लॉन्च करती है, लेकिन इस बार कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जापान की मीडिया कंपनी निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, एपल साल 2026 के अपने एनुअल इवेंट में आईफोन 18 का बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा। कंपनी इसे साल 2027 की पहली छमाही तक के लिए टाल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल ने यह फैसला मैमोरी चिप और अन्य मटेरियल्स की बढ़ती कीमतों के कारण लिया है। कंपनी अपने संसाधनों को ऑप्टिमाइज करना चाहती है ताकि, प्रीमियम मॉडल्स से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाया जा सके। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन और एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने भी संकेत दिए हैं कि एपल इस साल आईफोन 18 को रिलीज करने के मूड में नहीं है। इसके बजाय, कंपनी आईफोन 18e मॉडल के साथ इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। एपल के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह उसका पहला फोल्डेबल आईफोन भी है।

कॉन्फिडेंट-ग्रुप चेयरमैन ने आईटी-रेड के दौरान गोली मारकर खुदकुशी की

9000 करोड़ की संपत्ति, प्राइवेट जेट, 200 से ज्यादा कारों के मालिक थे

बेंगलुरु, एजेंसी

कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने शुक्रवार को सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 3.15 बजे हुई। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों से इनकम टैक्स (IT) विभाग की तलाशी चल रही थी। रॉय की सुसाइड के बाद आयकर अधिकारी रेड की प्रोसेस बीच में छोड़कर चले गए। रॉय की नेटवर्थ 9 हजार करोड़ रुपए थी। उनके पास प्राइवेट जेट और 200 से ज्यादा लग्जरी कारें थीं। इनमें से 12 रोल्स रॉयस भी शामिल हैं। मूल रूप से केरल के रहने वाले रॉय का कारोबार कर्नाटक और दुबई में फैला था। कॉन्फिडेंट ग्रुप केरल और कर्नाटक का रियल एस्टेट डेवलपर है। पुलिस ने बताया कि मौके पर कोई IT अधिकारी मौजूद नहीं था। बेंगलुरु पुलिस जांच के तौर पर IT विभाग से जरूरी जानकारी लेगी। उधर, रॉय की पत्नी और बेटा शनिवार को बेंगलुरु के बॉवरिंग अस्पताल में पोस्टमॉर्टम सेंटर पहुंचे। पुलिस कानूनी आधार पर देख रही है कि इसे अप्राकृतिक मौत के तौर पर दर्ज किया जाए या आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं लगाई जाएं। कमिश्नर ने पुष्टि की कि कॉन्फिडेंट ग्रुप के एक डायरेक्टर ने पहले ही शिकायत दर्ज करा दी है। ऑफिस कैम्पस से सबूत जुटाए जा रहे हैं। रिकॉर्ड और बयानों की जांच के बाद और मामला साफ होने की उम्मीद है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की मौत की हाई-लेवल जांच की जाएगी। केरल आयकर की टीम 3 दिन से सीजे (चिरियनकांडथ जोसेफ) रॉय के दफ्तर में कार्रवाई कर रही थी। रोज उनसे पूछताछ की जा रही थी। रॉय के बड़े भाई ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी के दबाव की वजह से उन्होंने सुसाइड की। आयकर अफसरों को जवाब देना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे भाई ने यह कदम उठाया। भाई के मुताबिक, रॉय पर कोई कर्ज नहीं था। केरल से आयकर टीम पहली बार 3 दिसंबर 2025 को आई थी और कुछ दिन बेंगलुरु में रुकी थी। इसके बाद वह 28 जनवरी को आई और सीजे रॉय को दुबई से बुलाया गया। रॉय के परिवार में पत्नी लिनी रॉय, बेटा रोहित और एक बेटी रिया हैं।

लखनऊ के 4132 बूथों पर बीएलओ रहेंगे मौजूद, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अंतिम मौका

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जिन नागरिकों का नाम अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है, उनके लिए रविवार को बड़ा मौका है। लखनऊ के 4132 से अधिक बूथों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां बीएलओ मतदाता सूची के साथ मौजूद रहेंगे और नाम जुड़वाने के आवेदन स्वीकार करेंगे। लखनऊ में अनंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद 12 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए हैं। छह जनवरी के बाद से अब तक करीब डेढ़ लाख नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर पर सभी की नजरें टिकी हैं। जिलाधिकारी ने लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र के तहत काशीराम ईको गार्डन स्थित वीआरसी, ईको गार्डन और सिंचाई विभाग के अतिविशिष्ट अतिथिगृह में बने सुनवाई कक्षों का निरीक्षण किया।

जरूरी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदक को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या, माता-पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां देनी होंगी। यदि नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन माता-पिता या दादा-दादी का नाम सूची में दर्ज है, तो गणना प्रपत्र में संबंधित रिश्तेदार का विवरण भरना होगा। यदि किसी बूथ पर बीएलओ उपलब्ध नहीं मिलते हैं, तो मतदाता https://voters.eci.gov.in वेबसाइट या ईसीआई-नेट ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने साफ किया है।

18 वर्ष पूरे होने से पहले भी कर सकते हैं आवेदन

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन युवाओं की उम्र अभी 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी आवेदन का अवसर दिया जा रहा है। जिनकी उम्र एक अप्रैल 2026, एक जुलाई 2026 या एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे भी फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

व्यक्तिगत सुनवाई से दी गई छूट

निर्वाचन आयोग ने नोटिसों की सुनवाई के दौरान मतदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दी है। इस व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करने के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

4132 बूथों पर लगेगा विशेष शिविर

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. के निर्देश पर रविवार को जिलेभर के 4132 बूथों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बीएलओ और सुपरवाइजर बूथों पर मौजूद रहेंगे।

66 मतदाता सूची में नए नामों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने प्रशासन से नए वोटरों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। पार्टी का कहना है कि कुछ मतदाताओं के पते सही तरीके से दर्ज नहीं किए गए हैं, इसलिए दोबारा सत्यापन कराना जरूरी है।

दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने जाना लोकतंत्र का जीवंत स्वरूप

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को शिक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर ठोस एवं संवेदनशील प्रयास कर रही है। इसी क्रम में डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का शैक्षिक भ्रमण किया। इस शैक्षिक भ्रमण में विश्वविद्यालय के ईएमईटी (EMET) पाठ्यक्रम के दृष्टिबाधित अभ्यर्थी, उनके प्रशिक्षक, स्वयंसेवक तथा हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन (HTBF) के समन्वयक डॉ. विजय शंकर शर्मा सम्मिलित रहे। एचटीबीएफ के सहयोग से आयोजित इस भ्रमण का उद्देश्य दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को

लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, विधायी प्रक्रिया एवं शासन व्यवस्था की प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना था। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया, सदन में चर्चा एवं निर्णय लेने की प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विधानसभा भवन की फोटो गैलरी के माध्यम से उन्हें प्रदेश के पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों, ऐतिहासिक घटनाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं से अवगत कराया गया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधानसभा का विशेष स्पर्शनीय (टैक्टाइल) मॉडल प्रदर्शित किया गया, जिससे विद्यार्थियों ने स्पर्श के माध्यम से विधानसभा भवन की संरचना, आकार और आंतरिक व्यवस्था को समझा। इसके पश्चात विधानसभा कक्ष का भ्रमण कराते हुए सत्तापक्ष, विपक्ष, मीडिया दीर्घा, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था तथा अध्यक्ष (स्पीकर) की भूमिका और सदन संचालन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को विधानसभा में प्रयुक्त आधुनिक डिजिटल प्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगे डिजिटल पैनल, हेडफोन एवं डेस्क के माध्यम से प्रश्न पूछने, मतदान करने और सदन की कार्यवाही संचालित होने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा सरल, सहज और संवेदनशील भाषा में उत्तर दिया गया।

फास्ट न्यूज

इदरीस बिरयानी पर ₹15 हजार का जुर्माना

लखनऊ। लखनऊ में इदरीस बिरयानी की दुकान पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दुकान के आसपास गंदगी फैली हुई थी। प्लास्टिक में सामान भी बेचा जा रहा था। नगर निगम की टीम निरीक्षण करने पहुंची तो यह सब देखकर जुर्माना लगा दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि इस आदत का प्रदर्शन दोबारा न किया जाए। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने, गंदगी फैलाने और तंबाकू अधिनियम के उल्लंघन कार्रवाई जारी है।

बच्चा चोर कहकर बुलाई पुलिस, तीसरी मंजिल से कूदा युवक

झांसी। झांसी में शुक्रवार शाम को एक युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वो अपने दोस्त से मिलने आया था। घर के बाहर पड़ोसी के 10 साल के बच्चे को गोद में उठाकर खिलाने लगा। बच्चा चोर समझकर लोगों ने शोर मचाया। उसका पीछा किया। वह घबराकर दोस्त के किराए के घर में छिप गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर वह डर गया। तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसके दोनों पैर और सिर में चोट आई है। पुलिस उसको जिला अस्पताल ले गई। जहां इलाज के बाद परिजन उसे अपने साथ ले गए। पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के डडियापुरा स्थित मां दुर्गा कॉलोनी का है। डडियापुरा की मां दुर्गा कॉलोनी निवासी वर्षा साहू ने बताया- हमारे पड़ोस में विनोद कुशवाहा का मकान है।

खेसारी पर पवन सिंह का फूटा गुस्सा

वाराणसी। भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार्स के बीच जुबानी जंग जारी है। वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा- मेरे छोटे भाई सब चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मुझे मत बोलने दो, क्योंकि मैंने बोला था ना...जो बोलता है, उसे बोलने दो। मैं हर किसी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता।

लखनऊ के मॉडल वार्डों में लोगों को आएंगे कॉल

नगर निगम लेगा कूड़ा कलेक्शन की जानकारी

नगर निगम के सदन में पार्षद मनीष ने मॉडल वार्ड में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया था।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में 16 मॉडल वार्ड बनाए गए हैं। इन वार्डों के जोनल अधिकारी कूड़ा कलेक्शन 90 फीसदी से अधिक करने का दावा कर रहे हैं। अब नगर निगम की तरफ से इस दावे की क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी। इसमें दूसरी टीमों से इलाकेवार रिपोर्ट ली जाएगी। टीमें मॉडल वार्ड में जाकर यह पता करेंगी कि कूड़ा उठता है या नहीं। इसके साथ ही रैंडम कॉल से भी लोगों से उनके इलाके में कूड़ा कलेक्शन, साफ-सफाई की जानकारी ली जाएगी। इसमें सभी गलियों को कवर करने की तैयारी है। मॉडल वार्ड का सफल प्रयोग शुरू होने के बाद इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा। इन वार्डों में कूड़ा कलेक्शन के साथ ही साफ सफाई को

भी अव्वल बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। वार्डों की क्रॉस चेकिंग होने के बाद में इसे पूरे लखनऊ में लागू करने की तैयारी है। ताकि शहर में कूड़ा कलेक्शन के साथ में अन्य सुविधाओं का एक मॉडल तय किया जा सके। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि फरवरी में मॉडल वार्ड की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें सुविधाओं में सुधार कराया गया है। इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। लखनऊ में हर जोन से दो वॉर्ड को मॉडल बनाने के लिए चुना गया है।

नाम पूछकर माथे पर मारी गोली

एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी पर बदमाशों का हमला, बोले- यही है मारो

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में दो बदमाशों ने एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी के माथे पर गोली मार दी। वह पत्नी के साथ अपने रेस्टोरेंट में थे। रात करीब 10 बजे वह रेस्टोरेंट बंद करने लगे। यहां का कुछ सामान रखने अपनी कार तक गए। वहां दौड़कर आए दो लोगों ने उनका नाम पूछा। इस पर उन्होंने पलटकर देखा। उनके पलटकर देखते ही दो में से एक बदमाश ने कहा- यही है मारो। इतना सुनते ही दूसरे वाले ने फायर कर दिया। गोली रिटायर्ड अधिकारी की दाहिनी आंख के ऊपर माथे पर लगी। गोली लगते ही वह गिर पड़े और बदमाश वहां से भाग गए। मामला सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के शॉपिंग स्क्वायर-2 कॉम्प्लेक्स का है। घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक (60) के रूप में हुई। उन्हें उनकी पत्नी ने स्थानीय लोगों की मदद से मेदांता अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि घायल की पत्नी

पुलिस सूचना के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। यहां खून बिखरा हुआ दिख रहा है।

मिथिलेश की शिकायत पर 2 अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। जांच जारी है। सुशांत गोल्फ सिटी के शॉपिंग स्क्वायर में अवधेश अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट चलाते हैं। हमलावर रेस्टोरेंट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अवधेश को गोली मारकर भाग गए। गोली लगने के बाद अवधेश गिरे जरूर लेकिन संभलते हुए खड़े हुए और अपने रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। पत्नी के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया है कि गोली

उनके माथे में ही फंसी हुई है। डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे की घटना है। घायल अवधेश संतकबीरनगर के हावपुर गड़ारी थाना बखिरा के रहने वाले हैं। उनकी एक बेटी कनाडा में हैं और बेटा पुणे में है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रादेशिक फल-शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2026 की जजिंग शुरू

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में आयोजित की जा रही 6 से 8 फरवरी तक तीन दिवसीय प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी–2026 के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के उद्यानों एवं गृहवाटिकाओं की प्रतियोगिता हेतु जजिंग कार्य का शुभारम्भ 31 जनवरी 2026 को किया गया, जो 01 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा।निदेशक उद्यान श्री बीपी राम ने बताया कि इस वर्ष जनपद लखनऊ से विभिन्न श्रेणियों में कुल 243 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रतियोगिता में शासकीय, अर्धशासकीय, संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर विकसित उद्यानों और गृहवाटिकाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है।प्रदर्शनी के अंतर्गत उद्यान विभाग, भारतीय सेना, रेलवे, पीएसी मुख्यालय, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, एसजीपीजीआई, आरडीएसओ, आईआरटीएम, जन भवन सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के उद्यानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत उद्यान प्रेमियों द्वारा विकसित गृहवाटिकाओं

ने भी प्रतियोगिता में विशेष आकर्षण उत्पन्न किया है।इसके अतिरिक्त, शहर के ऐतिहासिक एवं विरासत स्थलों जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सहादत अली ख़ां का मकबरा आदि के उद्यानों को भी प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में सम्मिलित किया गया है, जिससे प्रदर्शनी को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है।प्रतियोगिता में प्राप्त सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के औद्यानिकी से संबंधित प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों, साथ ही प्रदेश उद्यान विभाग में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त विषय विशेषज्ञों से गठित निर्णायक मंडलों द्वारा किया जा रहा है।

जगन्नाथ पुरी से लौट रहे 6 की मौत

100 की स्पीड में ट्रक ने 2 ऑटो को टक्कर मारी, उछलकर 10 फीट दूर गिरे

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने जगन्नाथ पुरी से लौट रही सवारियों से भरे 2 ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद लोगों ने आरोपी ट्रक चालक को पकड़कर पिटाई कर दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ऑटो उछलकर सड़क किनारे करीब 10 फीट दूर पेड़ से टकरा गए। फिर गड्ढे में जाकर पलट गए। लोगों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। टेंपो बुरी तरह डैमेज होकर दो हिस्सों में बंट गया। उसकी छत उड़ गई। बताया जा रहा है कि टेंपो सवार लोग एक ही गांव के थे। जगन्नाथ पुरी से वापस आए थे। आगरा स्टेशन से अपने गांव जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर नशे में था। 100 की रफ्तार में जलेसर रोड की तरफ से लहराते हुए ट्रक आ रहा था। पहले एक ऑटो को टक्कर मारी। उसे 50 मीटर तक घसीटते ले गया। इसके बाद दूसरे ऑटो को टक्कर मार दी। एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया- हादसे की

ट्रक की टक्कर के बाद ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई।

हादसे के बाद घायल लोगों को बचाने के लिए लोग आगे आए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर शनिवार सुबह 11 बजे हुआ। थाना सहपयू के भादउ गांव के रहने वाले आठ लोग बिजो, लख्मीचंद, रणवीर सिंह, बिल्ला मिस्त्री, धनप्रसाद, विजय सिंह, उदयवीर सिंह और रामदत्त 20 जनवरी को जगन्नाथ पुरी गए थे। दर्शन करने के बाद सभी शनिवार को जबलपुर होते हुए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। सभी ने अपने गांव के लिए 2 ऑटो बुक किए। एक ऑटो शहीद खान चला रहा था। दूसरे के चालक की पहचान होना बाकी है। रामदत्त दवा लेने के लिए रास्ते में उतर गए। थोड़ी देर बाद नगला चंदन जलेसर रोड पर सामने से आ रहे ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धनप्रसाद और विजय गंभीर रूप से घायल हो गए। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रणवीर रिटायर्ड दारोगा बताए जा रहे हैं। दुखद घटना है। उन्होंने बताया- जैसा कि मुझे बताया गया दो ऑटो वाले ओवरटेक कर रहे थे। सामने से डंपर आ गया था। जिससे एक्सीडेंट हो गया था। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि 4 लोग घायल हैं। ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। ड्राइवर का मेडिकल कराया जा रहा है। बताया जा रहा कि सभी यात्री जगन्नाथपुरी के दर्शन करके लौट रहे थे।

स्वागत: कानपुर में कहा- शंकराचार्य से मिलने जाऊंगा, नारे लगे- देखो शेर आया

अफसरी छोड़कर अलंकार घर पहुंचे तो मां ने गले लगाया

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री शनिवार को कानपुर स्थित अपने आवास पहुंचे। केशव नगर स्थित घर पर पहुंचते ही परिजनों, समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। घर की महिलाओं ने शंखनाद कर उनका अभिनंदन किया, जबकि उनकी मां गीता अग्निहोत्री ने उन्हें माला पहनाकर गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान समर्थकों ने फूल-मालाओं से उन्हें लाद दिया और "देखो-देखो शेर आया" जैसे नारे लगाए। मौके पर मौजूद लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर नृत्य भी किया। पूरा माहौल उत्साह और जोश से भरा रहा। अलंकार अग्निहोत्री के कानपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर पहुंच गए। लोगों ने इसे 'सम्मान और संघर्ष की जीत' बताया। समर्थकों का कहना था कि उन्होंने अपने

आत्मसम्मान और धार्मिक मूल्यों के लिए पद छोड़कर एक साहसिक कदम उठाया है। अलंकार अग्निहोत्री ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें जनता के प्रेम और समर्थन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। 'तमसा संकेत' से बातचीत में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह दो से तीन दिनों के भीतर अपनी आगे की रणनीति तैयार करेंगे और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल शंकराचार्य की ओर से दिए जाने वाले किसी भी पद या जिम्मेदारी को स्वीकार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी पद की प्राप्ति नहीं, बल्कि समाज के हित में संघर्ष करना है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने अगले कदम को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब वह देश में लागू "एक और काले कानून" यानी SC-ST एक्ट की समीक्षा और वापसी के लिए आंदोलन करेंगे। उनका दावा है कि इस कानून के तहत करीब 95 प्रतिशत शिकायतें फर्जी होती हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग कर सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य, भूमिहार और ओबीसी वर्ग के लोगों को परेशान किया जाता है।

अलंकार बोले- मोदी-शाह की सोची-समझी साजिश

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा- यूजीसी रेग्यूलेशन 2026 को भारत सरकार के गजट में जारी किया गया। मैं अब साफ तौर पर नाम लेना चाहूंगा, ये मोदी और शाह की सुनियोजित, सोची-समझी साजिश है। उन्होंने एक ऐसा गजट तैयार कराया, जिससे जनरल और OBC को आपस में लड़वा सकें। साजिश रची गई कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए। बजरंगबली का आशीर्वाद था कि हम लोगों का विवेक समय पर जाग उठा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक लग सकी।

सभी पार्टियां हमारे संपर्क में हैं

राजनीतिक दलों के संपर्क में रहने के सवाल पर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा- हमारे संपर्क में सभी पॉलिटिकल पार्टी, ब्राह्मण संगठन, किसान संगठन और सवर्ण समाज, OBC संगठन हैं। SC-ST के संगठन भी हमारे संपर्क में हैं।

पृष्ठ 01 का शेष...

ट्रम्प के फायदे के ...

इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एपस्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को 'मसाज' के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर यह बात अपने माता-पिता को बताई, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफ्री एपस्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि यह अकेला मामला नहीं है। धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई, जिन्होंने एपस्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एपस्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एपस्टीन यहां हाई-प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं। एपस्टीन अपने निजी जेट 'लोलिता एक्सप्रेस' से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वह लड़कियों को पैसों-गहनों का लालच और धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें एपस्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एपस्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वह जेल से बाहर जाकर काम भी कर सकता था। साल 2009 में जेल से आने के बाद एपस्टीन लो प्रोफाइल रहने लगा। ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। साल 2017 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइंस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट्स छापीं। इसमें बताया गया कि वाइंस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। 80 से ज्यादा महिलाओं ने वाइंस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू (मेरे साथ भी शोषण हुआ) के आरोप लगाए। इसमें एंजेलीना जोली, सलमा हायेक, उमा थरमन और एश्ले जुड जैसे बड़े नाम थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर '#MeToo' लिखकर अपने शोषण की कहानियां शेयर कीं। इसमें वर्जीनिया ग्रिफे नाम की युवती भी थी। उसने एप्सटीन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसके साथ 3 साल तक यौन शोषण हुआ था। इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने उसके खिलाफ शिकायत की।

पीएम मोदी के ...

मेल को 'बिल्ली हाल' के नाम से भेजा गया। अंदर लिखा- आज 3-4 स्कूलों में बम धमाका होगा। हम गुरु रविदास जी की फुल रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मोदी खालिस्तान वालों का दुश्मन है। खालिस्तानियों का बाबा निरंजन दास के साथ कोई गिला-शिकवा नहीं है। मसला मोदी का है। निज्जर की मौत का जिम्मेदार कौन है...बदला...बदला...बदला। निशाने पर डेरा बल्लां। उधर, पीएम मोदी 1 फरवरी को पौने 4 बजे जालंधर पहुंचेंगे और 2 बड़ी सौगात देंगे। इसमें आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा के चलते पुलिस ने पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम का जालंधर के डेरा बल्ला में करीब 40 मिनट रुकने का प्लान है। इसमें उनकी 15 मिनट की स्पीच भी शामिल है। इसके अलावा पीएम 10 मिनट तक डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात करेंगे। पंजाब लीडरशिप के साथ भी पीएम की 10 मिनट की मीटिंग होगी। इसके बाद पीएम दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। डेरा सचखंड बल्लां में पीएम मोदी के विजिट को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट डायवर्ट किए हैं। कई जगह पर ट्रैफिक के एग्जिट और एंट्री पाइंट बनाए हैं। 1 फरवरी को गुरु रविदास जयंती पर लाखों लोग डेरा बल्लां में पहुंचेंगे। इसके चलते जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे और डेरा बल्लां की ओर जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के चलते पीएम का रोड रूट नहीं रखा गया है, लेकिन इस दिन पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने से वीआईपी मूवमेंट रहेगी।

अजित चाहते थे ...

और हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते थे कि लोगों को न्याय मिले। NCP (SP) के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि बुधवार को हुए प्लेन क्रैश से पहले NCP के दोनों पक्ष बातचीत की एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच गए थे। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के खत्म होने के तुरंत बाद विलय की घोषणा किए जाने का प्लान था। अजित की रणनीति यह थी कि स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान माहौल का जायजा लिया जाए और पूरी तरह से विलय की घोषणा करने से पहले दोनों पार्टियों के वोट बैंक को मजबूत किया जाए। सूत्रों का कहना है कि विलय से कैबिनेट के गणित में मौलिक बदलाव आएगा। अगर विलय होता है, तो NCP (SP) के नेता राज्य के शासन और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस मर्जर को पश्चिमी महाराष्ट्र के शुगर बाउल पर फिर से कब्जा करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

₹3000 खाने के बिल के लिए दो दोस्तों का मर्डर

गाजियाबाद में ढाबे के कर्मचारियों ने चाकू मारे, साथी जान बचाकर भागे

तमसा संकेत, एजेंसी

गाजियाबाद। गाजियाबाद में ढाबे पर दो दोस्तों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ढाबे के कर्मचारियों ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों युवक अपने तीन और दोस्त के साथ दो बाइकों से ढाबे पर पहुंचे। खाना खाया। आरोप है कि ढाबे के कर्मचारियों ने उनसे 3 हजार का बिल मांगा। इतना बिल सुनते ही युवक भड़क गए। उनकी मालिक और कर्मचारियों से कहासुनी हो गई। गुस्से में ढाबे के कर्मचारियों ने दोनों युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। मारपीट देखकर दोनों युवकों के साथी भाग गए। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना खोड़ा इलाके के वैष्णो ढाबे पर शुक्रवार देर रात हुई। मृतकों की पहचान सत्यम (25) और श्रीपाल (26) के रूप में हुई है। उपुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात 10

बजे वैष्णो ढाबा पर खोड़ा के रहने वाले सत्यम (25) और उसका दोस्त श्रीपाल (26) तीन और दोस्तों के साथ खाना खाने पहुंचे थे। उन्होंने वेज थाली ऑर्डर की। खाने के बाद स्टाफ ने बिल थमाया। बताया जा रहा है कि 3 हजार रुपये का बिल आया था। सत्यम और श्रीपाल ने कहा कि बिल ज्यादा आया है। इसे लेकर ढाबे वालों से कहासुनी हो गई। कहासुनी गाली-गलौज तक जा पहुंची। ढाबा मालिक ने अन्य कर्मचारियों को बुला लिया। वे सत्यम और उसके दोस्त श्रीपाल से मारपीट करने लगे। मारपीट होते देख उनके दोस्त भाग गए।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676